

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146 वर्ष: 32 संख्या: 180 प्रभात उदयपुर, रविवार 4 मई, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जातिगत जनगणना: मण्डल-कमण्डल सोच का विलय है

पर, इस विलय का क्या अर्थ निकलेगा, यह अभी अनिश्चितता के कोहरे में छिपा है, जिसका आंकलन करना, विशेषकर भाजपा के लिये बहुत मुश्किल है

–श्रीनंद झा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 3 मई। केन्द्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराये जाने का निर्णय लिये जाने के बाद, मंडल और कमंडल मुद्दों के विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके साथ ही, भाजपा के अन्दर इस बात को लेकर काफी बेचैनी है, क्योंकि पार्टी नेताओं द्वारा पहले जातिगत जनगणना की कड़ी आलोचना की गई थी, इसलिए अब चिंता है कि इस पर राजनैतिक खेल क्या होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर दूसरी-तीसरी पंक्ति के भाजपा नेता, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, पहले जातिगत जनगणना कराने के घोर आलोचक रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ की स्थिति खासतौर बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में “बटेंगे तो कटेंगे” का नारा दिया था तथा उनकी मानयता थी कि जातिगत जनगणना तो विपक्षी दलों की रणनीति है, जिससे

■ योगी आदित्यनाथ का नारा रहा है, “बटेंगे तो कटेंगे”, तो क्या यह नारा निरर्थक हो गया।

■ योगी आदित्यनाथ, “जातिगत जनगणना” का विरोध इसलिए कर रहे थे, क्योंकि उनकी सोच है कि जातिगत जनगणना, विपक्ष की रणनीति है, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए और यह आरक्षण, उनके अनुसार, हिन्दुओं का आरक्षण घटाकर दिया जायेगा।

■ भाजपा में यह भी सोच है कि जाति जनगणना दोधारी तलवार है। एक तरफ तो इस जनगणना ने कांग्रेस व विपक्ष का मुख्य चुनावी मुद्दा उनसे छीन लिया है दूसरी ओर इस निर्णय से भाजपा में भी अंदर ही अंदर काफी बैचैनी है तथा वैचारिक उथल-पुथल है।

हिन्दुओं की कीमत पर, मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद, योगी आदित्यनाथ ने “समग्र सामाजिक– आर्थिक विकास लाने के लिये शुरू की जाने वाली इस कार्यवाही के लिये प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त” निस्संदेह रूप से किया था, लेकिन उसके

बाद उन्होंने पूरी तरह चुप्पी धारण कर ली है। दूसरी तरफ, उनके उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कदम का स्वागत एवं यशोगान करने के लिये प्रैस कॉन्फ्रेंसोज आयोजित किये जा रहे हैं। भाजपा के अन्दर कुछ गुप्तों का मानना है कि जातिगत जनगणना कराने का निर्णय एक दोधारी तलवार है, जिसमें

जहाँ कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रचार के मुख्य आधार को तहस-नहस करने की क्षमता है, वहीं यह भाजपा के अन्दर भूचाल ला सकती है।

इन वर्गों का कहना है कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद, कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों की ओर से माँगों की बाढ़ आ जायेगी।

सरकार ने पहले आरक्षण नीति की समीक्षा करने तथा विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गई जातियों को चिन्हित करने के लिये जस्टिस रोहिणी आयोग गठित किया था। यद्यपि रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जाहिर है, राजनेताओं को यह डर था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से, वह मुद्दा फिर से हावी हो जाएगा, जो अब तक शांत था। भाजपा थिंक टैंक का मानना है कि चौँक अब जातिगत जनगणना करने का निर्णय ले लिया गया है, इसलिये रोहिणी आयोग की सिफारिशें एक स्वाभाविक उप-परिणाम के रूप में सामने आ जायेंगी।

पायलट पति अपनी पायलट पत्नी व बेटी को भरण पोषण भत्ता दे

जयपुर, 3 मई। जयपुर मेट्रो-प्रथम की फैमिली कोर्ट-एक ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में पायलट पति को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी, जो खुद पायलट है, को 80 हजार रूपए व बेटी को 60 हजार रूपए, अर्थात कुल 1.40 लाख रूपए हर महीने भरण-

■ फैमिली कोर्ट ने पायलट पत्नी को 80 हजार रूपए तथा बेटी को 40 हजार रूपए हर माह भरण पोषण के लिए देने के आदेश दिये।

पोषण की राशि दे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम भरण पोषण की यह राशि प्रार्थना पत्र दायर करने की तारीख 30 नवंबर 2024 से दो किस्तों में देय होगी और हर महीने की दस तारीख तक देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पत्नी के अंतरिम भरण पोषण हेतु दायर प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार जसूजा ने आदेश में कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक ही मुद्दे पर दुबारा याचिका दायर नहीं कर सकते

जयपुर, 3 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हटाने से जुड़े मामले में पुनः याचिका दायर करने वाले तीन याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए प्रमुख शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रभु दयाल व तीन अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की जानकारी में यह गड़बड़ी

■ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस ली। हाई कोर्ट ने शिक्षा समिति सचिव को कार्यवाही के आदेश दिये।

आने पर उन्होंने याचिका को वापस ले लिया।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) बीएस छाबा ने अदालत को बताया कि याचिका में शामिल याचिकाकर्ता योगेश, भंवर और रामस्वरूप ने पहले ही इस मुद्दे पर एक याचिका पेश की थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष देने को कहा था। तथापि, इस याचिका में पूर्व की याचिका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेजस्वी यादव ने प्र.मंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद

पत्र में तेजस्वी ने जुडीशियरी व प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की मांग की

–डॉ. सतीश मिश्रा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 3 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना से सम्बंधित त्याग की और भड़का दिया और न्यायपालिका व प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने मंडल आयोग की लम्बित सिफारिशों के तुरंत क्रियान्वयन की मांग की और कहा प्राइवेट सैक्टर, ठेकों और न्यायपालिका में जातिगत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार जाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। “तेजस्वी ने कहा संविधान ऐसे एक्शन का नैतिक और कानूनी आधार देता है।”

तेजस्वी ने कहा, हमारा संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से निर्देश देता है कि आर्थिक असमानता कम की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों का समान वितरण हो। जब हम जानेंगे कि कितने नागरिक वंचित समूहों

■ तेजस्वी का तर्क है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सैक्टर, भूमि सब्सिडी, टैक्स रियायतें आदि सरकारी सहायता का लाभ उठाता है। अतः कॉर्पोरेट जगत जो भी नौकरियां देता है या पदोन्नति देता है, उसमें देश की विविधता (कमजोर वर्ग) को भी पूरा लाभ मिलना चाहिये।

■ तेजस्वी ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में किये गये जातिगत सर्वे में उजागर हुआ कि ओबीसी व इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की संख्या 63 प्रतिशत है बिहार में, इस आंकड़े ने उन कई किंवदंतियों को नेस्तनाबूद कर दिया, जो समाज में यथास्थिति बरकरार करने के लिये फैलायी गई थीं।

■ तेजस्वी के अनुसार, संविधान में प्रावधान है कि समाज में आर्थिक विषमताएं खत्म हों तथा संसाधनों का “इक्विटैबल” वितरण हो। अतः जातिगत जनगणना के बाद, हम दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण आदि का पूरा लाभ दे सकेंगे।

से हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है तब अधिक सटीकता के साथ लक्षित

हस्तक्षेप तैयार किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र जो सार्वजनिक संसाधनों का प्रमुख

जारी कर रहे थे, पर एन.जी.टी. ने अपने आदेश से इस पर रोक लगा दी। परंतु हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो स्टेट इन्व्‍यारनमेंट इम्पैक्ट एसैसमेंट अर्थांरिटी (एस.ई.आई.ए.ए.) का गठन ही नहीं किया गया था और राजस्थान जैसे प्रदेश, जहाँ एस.ई.आई.ए.ए. का गठन तो किया गया था परंतु अधिकारियों द्वारा बजरी खनन करने के लिए दायर आवेदनों पर कई वर्ष तक कार्यवाही नहीं की गई, जिस वजह से कुछ ही आवेदनों को अस्वीकार किया गया और अधिकतर आवेदनों पर कोई फैसला ही नहीं लिया गया।

पाठकों को यह भी बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान रिटायर्ड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लाभार्थी रहा है, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकता। कांर्पोरेट कम्पनियों को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, रियायती दरों पर जमीन, बिजली पर सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन।

उन्होंने परिसीमन पर भी चिंता जताई और ओबीसी व ईबीसी के राजनैतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया, जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है उन्होंने कहा विधानसभाओं व संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए।

तेजस्वी ने लिखा कि “कई वर्षों तक आपकी सरकार व एनडीए के घटक दल जातिगत जनगणना को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, रियायती दरों पर जमीन, बिजली पर सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन।

महिला की हत्या करने वाले युवक को उम्र कैद की सजा

जयपुर, 3 मई। सत्र न्यायालय, महानगर प्रथम ने खो-नागोरियान थाना इलाके में धारदार चाकू से कई बार कर महिला का हत्या करने वाले अभियुक्त गौतम जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त

■ अभियुक्त ने दुकान से चाकू खरीद कर महिला के पेट पर कई गंभीर वार किये थे।

के खिलाफ हत्या का अपराध साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त ने भागन्ती देवी की हत्या करने के आशय से ही दुकान से चाकू खरीदा था और उस चाकू से उसके पेट पर कई बार गंभीर वार किए, ताकि हर स्थिति में उसकी मृत्यु हो सके। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एएन खान ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK